पापी अपने किये हुए से स्वयं ही ग्रस लिया जाता है । -आचार्य श्री देवेंद्र मुनि

प्रातःकाल
वैशाख शुक्ला 12, शुक्रवार, 16 मई, 2008

आतंकी मंसूबे

जयपुर बम विस्फोट आतंकवादियों की हताशा और हार का ताजा प्रमाण है। सेना और पुलिस से मात खा चुके संगठन अब मासूम जनता को अपनी हिंसा का शिकार बना रहे है। उन्हें किसी भी सूरत में पकड़कर सजा दिया जाना जरूरी है। आतंकवादियों का सामना करने के लिए जनता एकजुट है, इसका प्रमाण है कि मंगल को मंदिर या जुम्मे को मस्जिद के सामने बम फोड़कर साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रंग नहीं लाई। मालेगांव, वाराणसी, अजमेर या दिल्ली में आतंकवादी यह हथकंडा अजमाकर मुंह की खा चुके हैं। जनता जानती है कि आतंकवादियों का न तो कोई धर्म होता है और न ही जाति। अच्छा होगा यदि सरकार भी सजग हो जाए और ऐसे मौकों पर प्रतिद्वंद्विता भुलाकर राजनैतिक दल केवल राष्ट्रहित को सर्वोपरि महत्व दें। दुख की बात है कि प्रत्येक हमले के बाद ओछी राजनैतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। आतंकवाद का सामना मिलजुलकर ही किया जा सकता है। इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर असहयोग व उपेक्षा का जो आरोप लगाया है, यह उसका समय है। यह घड़ी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होने की है। विस्फोटों का कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, फिलहाल कहना कठिन है।

हां, वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों में इनकी गूंज अवश्य सुनाई देगी। दुख की बात यह है कि कई माह बीत जाने के बावजूद अजमेर शरीफ में हुए धमाकों का सूत्रधार पकड़ा नहीं जा सका है। यह हमारे जांच तंत्र की कमजोरी ही मानी जाएगी। जयपुर बम विस्फोटों के पीछे किस आतंकवादी संगठन का हाथ है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल बंगलादेश स्थित हरकत उल जिहाद-ए- इस्लामी तथा लश्कर व सिमी जैसे संगठन शक के घेर में हैं। पड़ोसी देशों में अस्थिर राजनैतिक माहौल का दुष्प्रभाव, सीधे-सीधे हमारी शांति व सुरक्षा पर पड़ता है। लगता है भारत विरोधी शक्तियां वहां जोर पकड़ रही हैं। जयपुर देश की पर्यटक राजधानी मानी जाती है। बम विस्फोट कर सैलानियों को भयभीत करने की भी कोशिश की गई है। आतंकवादियों पर शत-प्रतिशत काबू पाना तो कठिन है, किन्तु खुफिया तंत्र को मजबूत बनाकर तथा जांच एजेंसियों को चुस्त कर ऐसी वारदातों में कमी जरूर की जा सकती है। ■■■

नाम के लिए

किसी वक्त में मुंबई को महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित महानगर माना जाता था। पिछले दिनों महिलाओं के साथ बदसलूकी और बलात्कार के कई मामले सामने आए, कुछ में पुलिस वाले ही आरोपी थे। पुणे भी एक जमाने में ज्ञान और प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधि शहर था अब वहाँ भी अपराध और अपसंस्कृति काफी बढ़ गई है, लेकिन महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर. आर. पाटिल को इस बात की चिंता है कि कोई इन शहरों को बांबे या पूना नहीं कह दे। शिवसेना को यह चिंता हो तो समझ में आता है, शिवसेना हमेशा ही व्यर्थ के मुद्दों पर ही हो-हल्ला करती आई है लेकिन पाटिल तो शिवसैनिक नहीं है, वे इस आग को बुझाने की बजाय उसमें घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट था कि शिवसेना अपने वोट बढ़ाने के लिए उत्तर भारतीयों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी तभी राज ठाकर ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन की कोई औकात नहीं होती अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसके साथ नरमी नहीं बरती होती। अब राज ठाकर की प्रतिस्पर्द्धा में शिवसेना भी फिर से संकीर्ण मुद्दों की राजनीति करने लगी है और महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा सरकार बहुत छोटे स्वार्थों के लिए इस खतरनाक राजनैतिक प्रवृत्ति को हवा दे रही है।

मुंबई या पुणे या बंगलुरू जैसे स्थानीय परंपरागत नाम इस्तेमाल करने का तर्क तो समझ में आता है लेकिन यह तर्क जब दुराग्रह बन जाता है तो वह खतरनाक हो जाता है। कहीं कोई मुंबई को बांबे या पुणे को पूना कह दे तो उससे पहाड़ नहीं टूट पड़ता और यह आंदोलन करने का मुद्दा तो नहीं बनता। इन दिनों चुनावों की सुगबुगाहट हवा में है और कोई छोटा-मोटा मुद्दा भी विस्फोटक बन सकता है। ऐसे में सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे विस्फोटक मुद्दों को शुरू में ही कुचल डाले। लेकिन पाटिल जैसे लोगों को मुंबई की सुरक्षा की जगह उसके नाम का ख्याल ज्यादा है। ■■■

जरदारी की सरदारी में मुशर्रफ साथ

पाक मीडिया
जमनादास अख्तर

इसके चलते अब यह फैसला आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दूसरे ऐसे पार्टी प्रमुख ही कर सकते हैं। जरदारी अब लंदन चले गए हैं, जहां शरीफ, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड मिलबैण्ड से बातचीत कर रहे हैं। लगता है शरीफ को पटाने की कोशिश चल रही है। अगर यह जज वापिस ले लिए जाएं तो मुशर्रफ के बनाए हुए जजों का क्या होगा। क्या दोनों को संभालने में नया कानून लाया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 27 कर दें। एक जानकार फखरुद्दीन इब्राहिम ने इस कमेटी से इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। वह मुशर्रफ वाले जजों को निकालने के हक में हैं। दूसरे जानकार ए. एहसान ने कहा कि इन जजों को 'एडहाक' करार देकर केस दर केस पर फैसला किया जाए। नवाज शरीफ ने साफ किया कि सदन में बहस हो, लेकिन बाद में बिना किसी देर के एक सरकारी आर्डर के मुताबिक जजों को बहाल कर दिया जाए और इफ्तेखार चौधरी ही मुख्य जज रहें। उधर जरदारी कुछ साफ फैसला नहीं कर पा रहे। शायद मुशर्रफ के ऐहसानों से दबे मालूम होते हैं। 'डॉन' ने लिखा है कि अगर जरदारी मुशर्रफ के एहसानों का सिला देना चाहते हैं तो यह उनकी भूल है। उन्हें यह जानना चाहिए कि पीपीपी चुनाव जीत कर आई है, न कि पिछले दरवाजे से। उन्हें मिलीजुली सरकार के वायदे के मुताबिक इफ्तेखार चौधरी को और दूसरे निकाले हुए जजों को लाना चाहिए। अब इस मुद्दे को निपटाओ और लोगों के राशन, पानी, बिजली, सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए।

मिसाइलों की राजनीति

भारत की अग्नि मिसाइल के टेस्ट के दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने अपनी क्रूज मिसाइल हफत-।।। का टेस्ट करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। यह मिसाइल काफी नीचे उड़ती है और 'राडार' की पकड़ में नहीं आती। यानी अचानक आ सकती है 350 किलोमीटर तक। तहरीक-ए-तालिबान के बैयतुल्ला महसूद ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। आतंक की घटनाएं अब भी जारी हैं। पिछले हफ्ते इसके आतंकवादियों ने फिर दर्रा आदमखेल पर कब्जा कर अपने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। उसी के नायब अमीर मौलवी फकीर ने समाचार पत्रों और मीडिया को धमकी दे दी कि वह महिलाओं की बेहूदा तस्वीरें दिखानी छोड़ दें और यदि दो हफ्ते में ऐसा न हुआ तो तालिबानी अपनी ओर से कार्रवाई करेंगे। बन्नू में एक आतंकवादी युवा (जो स्कूटर रिक्शा पर सवारी के तौर पर बैठा था) ने आत्मघाती हमला कर दिया। इसके तो चीथड़े उड़ गए पर रिक्शा चालक और दो पुलिस वाले मौके पर ही मारे गए और बाकी काफी लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। यह आतंकवादी एजेंसी के सरकारी दफ्तर की ओर जा रहा था, रोके जाने पर आत्मघात किया। इसी तरह एक और हमले में नामालूम आतंकवादियों ने गोली चला कर स्वात के माटा शहर में दो पुलिसकर्मियों को मार गिराया। कराची से सुरक्षा एजेंसियों ने बयान दिया है कि बैयतुल्ला महसूद के पांच आतंकवादी कराची पहुंच गए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। स्वात में ही आतंकवादियों ने एक लड़कियों का स्कूल जला दिया। डॉन ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि सरकार की तहरीक-ए- तालिबान से जो 28 अप्रैल को बातचीत चल रही थी, वह टूट गई है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में अपने वायदों से हट रही है। पर्दे के पीछे दो महीनों की बातचीत में जो कामयाबी दिखाई पड़ रही थी, फौजों के हटाने के मुद्दे पर फैल हो गई। महसूद चाहते हैं कि सरकार न केवल महसूद क्षेत्रों में हट जाए, बलिपक सारे आदिवासी और दूसरे इलाकों से भी, जैस दर्रा आदमखेल और स्वात के इलाके। ये लोग अपनी बात मनवाना जानते हैं, पर क्या सरकार पीछे हटती रहेगी। अभी तक पाकिस्तानी राजदूत अजीजुद्दीन जिनका अपहरण 11 फरवरी को हुआ था, को छोड़ा नहीं गया।

आसिफ जरदारी के खिलाफ सब केस खत्म

सिंध हाईकोर्ट में जरदारी की शिकायत को सुनते हुए, सरकार ने साफ किया कि उन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ देश के अंदर और बाहर सभी केस वापिस ले लिए हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड और लंदन के केस भी शामिल हैं। अब वह सब तरफ से आजाद हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर अपनी हैरानगी जताते हुए दि नेशन और नवाएवक्त ने लिखा है कि क्या यह अपने आप हुआ। इससे पहले चुनाव कमीशन ने बाई इलेक्शन की तिथि जून से अगस्त तक टाल दी। इस पर काफी हंगामा हुआ और सभी समाचार पत्र कह रहे है कि यह सब शाहबाज शरीफ को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से रोकने की खातिर था। ■■■

कर्नाटक चुनाव में दिल्ली के दांव

महेश रंगराजन

अपने आकार और आबादी के कारण कर्नाटक का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। यही वजह है कि मुख्य दलों के आला नेता वहां वोटरों को रिझाने के लिए खट रहे हैं। आम चुनाव साल भर ही दूर है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य दलों के लिए यह अपनी ताकत और कल्पनाशीलता को आजमाने का मौका बन गया है। जनता दल सेकुलर के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और नई पीढ़ी के नेता कुमारस्वामी अपनी किस्मत आजमा रहे है। एक तरह से यह चुनाव एक बैरोमीटर है जो बताएगा कि देश में क्या होने वाला है। कुछ वैसे ही जैसे इस राज्य में नब्बे के दशक के मध्य में जनता दल की जीत ने संयुक्त मोर्चा सरकार का रास्ता तैयार कर दिया था। हालांकि 1983 तक यहां कांग्रेस को हराने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके पहले इसमें एक दरार तब जरूर पड़ी थी जब कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा के इंदिरा गांधी से मतभेद सामने आए थे। इसके बाद देवराज अर्स ने भारी तादाद में पार्टी से जनता को जोड़कर एक नए दौर की शुरुआत की। अर्स ने पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों को पार्टी में समाहित किया और पार्टी के पुरानी प्रभुवर्ग वाली छवि को तोड़ दिया। उन्होंने भूमि सुधार, आवास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं से पार्टी के आधार को इतना मजबूत बना दिया कि उसे आपातकाल के बाद की आंधी भी डिगा नहीं पाई, लेकिन 80 के दशक में गैर-कांग्रेसी सरकार ने सत्ता संभाली। रामकृष्ण हेगड़े ने अपने मशहूर मंत्री अब्दुल नजीर साहिब के साथ यहां पंचायतों को अधिकार देने का प्रयोग किया। 73वें संविधान संशोधन से काफी पहले ही वहां पंचायतों में औरतों को आरक्षण दे दिया गया था। इसके बाद से राज्य के वोटर कांग्रेस और जनता दल के घटकों को बारी-बारी से मौका देते रहे, लेकिन यह पैटर्न भी चार साल पहले टूट गया।

नब्बे का दशक आते-आते यहां भारतीय जनता पार्टी ने अचानक ही मजबूत होना शुरू कर दिया। शुरू में इसका आधार बांबे कर्नाटक क्षेत्र और तटवर्ती इलाकों के कारोबारी तबकों के भूस्वामियों तक सीमित था, लेकिन 1991 के चुनाव में उसे 28 फीसदी वोट मिले तो पहली बार लगा कि लिंगायत इसके झंडे तले जमा हो गए हैं। यहीं से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदुयरप्पा का उदय हुआ। इसके बावजूद 2004 के विधानसभा चुनाव में सत्ता समीकरण बदल गया क्योंकि सरकार बनाने की कुंजी सबसे छोटी पार्टी जनता दल सेकुलर के हाथ में आ गई। 224 सदस्यों वाले सदन में इसके महज 58 ही विधायक थे लेकिन इसी के बल पर एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने बड़े दलों को नाकों चने चबवा दिए। इसी का नतीजा है कि चुनाव इस बार एक साल पहले हो रहे हैं। कर्नाटक में 14 फीसदी वोटर मुसलमान हैं और वे सब कांग्रेस को ही वोट देते रहे हैं। इसका अपवाद सिर्फ 1994 है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण मुसलमान कांग्रेस से नाराज थे।

वैसे अपवाद तो इस बार के विधानसभा चुनाव भी हैं। प्रदेश में आमतौर पर स्थिर सरकार ही होती है। इसके पहले एक ही बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं। 1985 में हेगड़े ने लोकसभा के साथ ही प्रदेश विधानसभा चुनाव भी करवा लिए थे, जिसका उन्हें फायदा भी मिला और वे भारी बहुमत से चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार बहुमत के लिए तीनों दावेदारों को खासा उलझना पड़ रहा है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझी हुई है। उसे सबसे ज्यादा भरोसा बेंगलूरू सीट पर था, लेकिन वहां 44 फीसदी मतदान ही हुआ है। शहरी भारत के लिहाज से भी यह अच्छा प्रतिशत नहीं है और कांग्रेस व भाजपा दोनों के लिए ही यह बुरी खबर भी है। इसके अलावा पहले दौर की 89 ग्रामीण सीटों के लिए भारी मतदान हुआ है। कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ एक ही चीज है- इसके पास विभिन्न तबकों और समुदायों के बड़े-बड़े नेता है। मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार न होने का भी उसे फायदा मिल रहा है क्योंकि इस पद की इच्छा रखने वाले सभी नेता जीजान से जुटे हैं।

कांग्रेस के पास दो रुपए किलो चावल और गरीबों के लिए घर का वादा है तो जवाब में भाजपा ने उसमें कपड़े को भी जोड़ दिया है। वह बीपीएल कार्ड का दायरा बढ़ाने और उसमें मध्य वर्ग को लाने की बात भी कह रही है। महं गाई के चलते यह वादा भी लोगों को लुभा रहा है। इन दोनों में जिसकी भी जीत होगी उसका आत्मविश्वास राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा। इस लिहाज से जनता दल सेकुलर को दरकिनार करने में दोनों का साझा हित है, लेकिन यह आसान नहीं है। बीस महीने सत्ता में रहकर कुमारस्वामी ने ब्याज दरों को चार फीसदी तक घटा दिया था। उनके भाई एचडी रवन्ना पूरी कामयाबी से नंदिनी मिल्क कोऑपरटिव फेडरशन चला रहे है। पुराने मैसूर इलाके में उनकी जड़ें काफी मजबूत हैं। कर्नाटक में सबके दांव काफी बड़े है। कांग्रेस यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद से पिछड़े और वंचित तबकों में उसकी पकड़ बढ़ी है। उसके सामने शहरी आधार को फिर से हासिल करने की चुनौती भी है। डीलिमिटेशन के बाद से बेंगलुरू की सीटों की संख्या 12 हो गई है - विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 12 फीसदी, लेकिन अगर उसे बहुमत नहीं मिलता तो दो साल में यह नौवां राज्य होगा जहां इसे मात मिली है। इससे केंद्र की संप्रग सरकार कमजोर होगी। यह कर्नाटक ही था जिसने 1994 में नरसिंह राव सरकार को कमजोर बनाया था। तब भी महंगाई ही मुख्य मुद्दा था।

अगर इस चुनाव में भाजपा जीतती है तो वह एक राष्ट्रीय ताकत की प्रतिष्ठा हासिल कर लेगी। इससे आडवाणी की प्रामाणिकता भी पुख्ता होगी और संघ परिवार में उठ रही विरोध की आवाजों पर लगाम लगाने में कामयाब हो सकेंगे।

लेकिन भाजपा और कांग्रेस की टक्कर सीधी न हो इस कोशिश में देवेगौड़ा कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे है। उनकी पार्टी ने अगर अच्छी स्थिति हासिल की तो तीसर मोर्चे का कार्ड चल निकलेगा। फिर बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे वोटों और सीटों का दसवां हिस्सा चाहती हैं। यह मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन उनकी ऐसी कोशिश कांग्रेस को परशान भी कर सकती है। पिछली बार बसपा 112 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे चार फीसदी वोट मिले थे। इस बार वह सभी सीटों पर किस्मत आजमा रही है। वैसे राज्य में एक खतरा त्रिशंकु विधानसभा का भी है। अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। ■■■

अपने ही चक्रव्यूह में घिरे अर्जुन सिंह

रामशास्त्री

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी मंडली के सदस्यों और मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह के मध्य महासमर छिड़ते ही पार्टी दिग्गजों ने नई घेराबंदी की है। पार्टी के महारथी चतुर सुजान अर्जुन सिंह को राजनीतिक 'चक्रव्यूह' में ध्वस्त करने में लगे है।

पार्टी में चतुर सुजान अर्जुन सिंह खेमे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माखनलाल फोतेदार, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री अजय माकन, दिल्ली के बिजली मंत्री हारून यूसुफ, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुंवर नटवर सिंह, आंध्रप्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महामंत्री एवं रिश्तेदार राधोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, हरियाणा के मंत्री वीरेन्द्र सिंह, पंजाब के जगमीत बराड़, बाल भवन के पूर्व अध्यक्ष रामशरण जोशी, अ.भा.कां.क. स्वतंत्रता सेनाली सैल के शशिभूषण, पूर्व आईएएस अशोक वाजपेयी, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान समिति के संयोजक एवं सुपुत्र अजय सिंह आदि प्रमुख माने जाते है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और पार्टी के महामंत्री दिग्विजय सिंह के लिए अर्जुन वाणी ने इधर कुआं, उधर खाई की स्थिति उत्पन्न की है। अर्जुन सिंह की शतरंजी चालों से प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री शिवराज पाटिल, वाणिज्य मंत्री कमलनाथ, पार्टी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेश पचौरी, मप्र विधानसभा में विपक्ष की नेता जमुना देवी, पूर्व मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, संचार राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा आदि खेमे विरोध में है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव खेमा लंबे समय से अर्जुन सिंह से दो-दो हाथ करने के अवसर की तलाश में है।

नरसिम्हा राव खेमे का आरोप है कि अर्जुन खेमे के कारण दक्षिण गौरव नरसिम्हा राव का शवदाह दिल्ली में नहीं करने दिया गया। इसके उलट चन्द्रशेखर का शवदाह दिल्ली में संपन्न हुआ। अर्जुन खेमा इस आरोप को निराधार कह रहा है। नरसिम्हा राव खेमे ने अर्जुन सिंह के 1984-2008 के कच्चे चिट्ठे में सनसनीखेज जानकारी दी है। नरसिम्हा राव खेमे ने अर्जुन सिंह की नेहरू खानदान और कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े किए है। खेमे का पहला यक्ष प्रश्न यह है कि 1985 में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय के बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तत्काल बाद अर्जुन सिंह को राज्यपाल बनाकर क्यों भेजा गया। क्या सन् 1984 के लोकसभा चुनाव विजयी राजपूत सांसद गोलबंद हो रहे थे। अर्जुन सिंह खेमा इन आरोपों को खारिज करता है। यह भी रहस्यमय पहेली है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने राज्यपाल के पद से हटाकर अर्जुन सिंह को पार्टी में उपाध्यक्ष एवं प्रकारांतर में संचार मंत्री आदि पद क्यों दिए। यानी 1985 से 1989 में राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह के पद 5 बार क्यों कर बदले। इसके अलावा यक्ष प्रश्न यह है कि राजीव गांधी की मानव बम थनु से निर्मम हत्या के पश्चात सोनिया गांधी ने प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंह, तिवारी की प्रधानमंत्री की दावेदारी को ठुकरा कर पी.वी. नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री क्यों मनोनीत किया। स्वाभाविक रूप से सन् 1991 में सोनिया गांधी ने नेहरू खानदान एवं कांग्रेस के प्रति अधिक प्रतिबद्ध नरसिम्हा राव को माना। अचरज की बात यह है कि उस समय प्रधानमंत्री की दौड़ में मराठा क्षत्रप शरद पवार भी थे। सन् 1991 से अर्जुन सिंह खेमे में भावी प्रधानमंत्री के लिए बिसात रची। उन्होंने सन् 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर इन्द्रप्राश फैंका। कांग्रेस की अल्पसंख्यकों में छवि को खंड-खंड करने में उनके खेमे का बहुत योगदान रहा। अंत में सोनिया गांधी का नाम लेकर अर्जुन सिंह ने 1999 में तिवारी कांग्रेस का गठन किया। सन् 1996 के लोकसभा चुनाव में तिवारी कांग्रेस के तीन सांसद शीशराम ओला, सतपाल महाराज आदि चुने गए, लेकिन उनकी वोटकटुवा भूमिका से कांग्रेस के 40 प्रत्याशी हारे। परिणामस्वरूप कांग्रेस गठबंधन सरकार के सपनों पर पानी फिरा।

सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में लौटे अर्जुन सिंह खेमे ने डैने फैलाए। उनके खेमे के नारायण दत्त तिवारी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बने। मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह के यहां शरणगत हुए। अर्जुन खेमे का नेहरू परिवार से मोहभंग सन् 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय हुआ। खेमे को अपेक्षा थी कि सोनिया गांधी अर्जुन सिंह को प्रधानमंत्री मनोनीत करेगी। आठवां आश्चर्य यह रहा कि नरसिम्हा रावके पट्टशिष्य डा. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया। इतना ही नहीं सोनिया गांधी द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पार्टी के वरिष्ठतम नेता कहलाने वाले अर्जुन सिंह को नहीं मिले। उन्हें मामूली मंत्रालय मिला। सोनिया गांधी ने अर्जुन सिंह के 75वें वर्ष जन्मदिन पर उन्हें राजनीति से सन्यास लेने की कड़वी सलाह दी। उनके खेमे के मंत्री नटवर सिंह इराक तेल कांड में हटाए गए। दूसरे तिवारी महाराज को राज्यपाल बनाकर इतिश्री की गई। तीसरे शीला दीक्षित और महामंत्री अशोक गहलोत में भीषण युद्ध चल रहा है। उनके रिश्तेदार दिग्विजय के खिलाफ मध्यप्रदेश के दिग्गज एकजुट है।

अर्जुन सिंह द्वारा विद्यालयों में वंदेमातरम विवाद का विरोध देशभर के मुस्लिम संगठनों ने किया। ओबीसी आरक्षण महाविवाद से क्षेत्रीय दलों राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल (यू), जनता दल (सेकुलर), राष्ट्रीय नैशनल लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल आदि का जातीय आधार सशक्त हुआ। फलस्वरूप सोनिया गांधी और अर्जुन सिंह खेमे के बीच ''दुर्लध्य खाई'' निर्मित हुई। अर्जुन ने इस खाई कोपाटने के चक्रव्यूह में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री घोषित कर नया बखेड़ा किया। सोनिया गांधी ने रक्षात्मक रूख अपनाया इससे घबराकर ही अर्जुन खेमे ने आत्मकथा के जरिये नया गोल दागा है। ■■■

प्रणव दा एक कम्प्यूटर

विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी सचिन तेंदुलकर के बड़े प्रशंसक है। राष्ट्रपति भवन में पदम अवार्ड समारोह में पहले सचिन प्रणव दा के पास गए और कहने लगे 'मैं आपसे मिलने का बहुत इच्छुक था, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, आप तो लाइव कम्प्यूटर हो।

प्रणव दा मुस्कराए और कहने लगे 'तुम सचिन रमेश तेंदुलकर हो, तुम्हारा जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ, मैं 5 फरवरी 1972 को कैबिनेट मंत्री बना यानि तुम्हारे जन्म से पहले तुमने बहुत कम उम्र में पुरस्कार जीते।'

मनमोहिनी नीति

मनमोहन सिंह भ्रम में है कि नया सीबीआई निदेशक जुलाई में नियुक्त किया जाए या वर्तमान निदेशक विजय शंकर का कार्यकाल बढ़ाया जाए। वह जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे है तथा अगले वर्ष चुनाव होने है। डा. मनमोहन सिंह नया निदेशक नहीं चाहते जिसका कार्यकाल दो वर्ष होगा। वह नई शिकार सरकार को अपनी पसंद का निदेशक चुनने से वंचित नहीं रखना चाहते।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का होना चाहिए। चर्चा है कि मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी को भी नहीं बदलना चाहते जिनका कार्यकाल 30 सितम्बर को पूरा हो रहा है। यह अलग बात है कि इन दोनों पदों के लिए लाबिंग शुरू हो चुकी है तथा रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, आईएमएफ के कार्यपालक निदेशक डा. आदर्श किशोर तथा वित्त सचिव डी. सुब्बाराव के नाम चर्चा में है।

सीबीआई निदेशक के पद के लिए केन्द्रीय विजीलैंस आयुक्त ने तलाश शुरू कर दी है। आयुक्त प्रित्युष सिन्हा तथा उनके दो सहयोगी सुधीर कुमार तथा रंजना कुमार जून में साक्षात्कार करेंगे और 1993, 1974 व 1975 के बैच के आईपीएस अधिकारी चुनेंगे। वह गृह मंत्रालय को इन अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने को लिख रहे है। लगभग 45 आईपीएस अधिकारी इसमें चुने जाएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह पैनल अंतिम निर्णय के लिए तीन नामों की सिफारिश करेगा।

नौसीखिए नौकर

सियासत के सूरमा हैं तो भला किसी दूसरे की बड़ी लकीर को कैसे सह सकते हैं। नीतीश कुमार का तो मिजाज ही अलग ठहरा। दूसरो की लकीर को न मिटा कर अपनी बड़ी लकीर खींचने में मजा आता है। जिसने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की उसे बिहार के मुख्यमंत्री ने औकात बता दी।

वाकया हाल ही का है। आईएएस अफसर अजय कुमार नीतीश के मुंह लगे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमे के सचिव थे तो खासी सक्रियता दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री की मंशा भांप वैज्ञानिकों के सम्मेलन की योजना बनाई थी। उसमें वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बने एपी जे अब्दुल कलाम को भी आमंत्रित कर डाला। सहमति भी मिल गई कलाम की। सोचा था अजय ने नितीश उनके इस कदम से खुश होकर पीठ थपथपाएंगे। आखिर रेलमंत्री के नाते अब्दुल कलाम नीतीश के निमंत्रण पर राष्ट्रति रहते बिहार आए थे। फिर मुख्यमंत्री बने तो कलाम को बुलाया। लेकिन खुद बुलाना अलग बात हुई, उनका कोई अदना अफसर अपने बढ़ाए, इसे भला कैसे बर्दाश्त करते नीतीश। सो ईनाम तो नहीं मिल, खुड्डेलाइन जरूर लगा दिए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमे से तो रुखसती हुई ही, राजस्व बोर्ड जैसी महत्वहीन तैनाती मिली। काश अजय कुमारे औरों के अनुभव से सबक किया होता। अतीत में भी तो कई आईएएस और आईपीएस अफसर सिर उठाते ही दरकिनार कर दिए थे। नीतीश कुमार ने। ■■■

एक नजर